

रीवा जिले में शहरीकरण एवं औद्योगीकरण का सामाजिक जीवन पर प्रभाव

(एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

डॉ. अखिलेश शुक्ला

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय रीवा
जिला-रीवा (म.प्र.)

सारांश-

प्रस्तुत शोध पत्र रीवा जिले में शहरीकरण एवं औद्योगीकरण की प्रक्रिया तथा उसके सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जिसमें जनगणना प्रतिवेदन, जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के प्रतिवेदन, जिला उद्योग केंद्र रीवा के अभिलेख तथा नगर निगम रीवा के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। अध्ययन में सन् 1991 से 2021 तक की अवधि में जिले की नगरीय जनसंख्या, औद्योगिक इकाइयों, व्यावसायिक संरचना, साक्षरता दर, महिला श्रमशक्ति सहभागिता एवं परिवार संरचना में आए परिवर्तनों का प्रवृत्ति-विश्लेषण किया गया है। निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि शहरीकरण एवं औद्योगीकरण की प्रक्रिया ने रीवा जिले की पारंपरिक सामाजिक संरचना, विशेष रूप से संयुक्त परिवार व्यवस्था, व्यावसायिक स्वरूप एवं महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक भूमिका को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है, साथ ही इसके परिणामस्वरूप कुछ सामाजिक समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं। अंत में सुव्यवस्थित शहरी एवं औद्योगिक विकास हेतु उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

मुख्य शब्द-

शहरीकरण, औद्योगीकरण, सामाजिक जीवन, रीवा जिला, सामाजिक परिवर्तन, परिवार संरचना, व्यावसायिक संरचना।

प्रस्तावना-

शहरीकरण एवं औद्योगीकरण आधुनिक सामाजिक परिवर्तन की दो प्रमुख एवं परस्पर संबद्ध प्रक्रियाएँ हैं, जिन्होंने विश्व भर के समाजों की संरचना, कार्यप्रणाली एवं मूल्य-व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया है। औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं, जिसके कारण ग्रामीण जनसंख्या का नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास होता है, जिससे नगरीय जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया के साथ-साथ पारंपरिक सामाजिक संस्थाओं, विशेष रूप से परिवार, जाति एवं व्यवसाय की संरचना में भी उल्लेखनीय परिवर्तन देखे जाते हैं।

मध्यप्रदेश का रीवा जिला बघेलखण्ड-विंध्य क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं आर्थिक केंद्र है। पिछले तीन दशकों में रीवा जिले में सीमेंट उद्योग, ऊर्जा उत्पादन इकाइयों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के साथ-साथ शिक्षा एवं प्रशासनिक सेवाओं के विस्तार ने नगरीय क्षेत्र के विस्तार को गति दी है। रीवा नगर एवं आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या के सघन होने से यहाँ की पारंपरिक सामाजिक संरचना पर भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि शहरीकरण एवं औद्योगीकरण की इस प्रक्रिया का व्यवस्थित विश्लेषण किया जाए, जिससे यह समझा जा सके कि इन प्रक्रियाओं ने रीवा जिले के सामाजिक जीवन, विशेष रूप से परिवार संरचना, व्यावसायिक स्वरूप, शिक्षा, महिलाओं की भूमिका एवं सामाजिक समस्याओं को किस प्रकार प्रभावित किया है। इसी उद्देश्य

को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर रीवा जिले में शहरीकरण एवं औद्योगीकरण के सामाजिक प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

शोध पत्र का उद्देश्य-

प्रस्तुत शोध पत्र के प्रमुख उद्देश्यों में रीवा जिले में विगत तीन दशकों में हुई शहरीकरण एवं औद्योगीकरण की प्रवृत्ति का अध्ययन करना, जिले में स्थापित प्रमुख औद्योगिक इकाइयों तथा उनके द्वारा सृजित रोजगार के स्वरूप का विश्लेषण करना तथा इस प्रक्रिया का जिले की व्यावसायिक संरचना, परिवार संरचना, साक्षरता दर एवं महिला श्रमशक्ति सहभागिता पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अध्ययन का उद्देश्य शहरीकरण एवं औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली सामाजिक समस्याओं की पहचान करना तथा संतुलित एवं सुव्यवस्थित शहरी-औद्योगिक विकास हेतु उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करना भी है।

महत्व-

प्रस्तुत अध्ययन का महत्व इस दृष्टि से अधिक बढ़ जाता है कि रीवा जिला वर्तमान में मध्यप्रदेश के तीव्र गति से शहरीकृत होने वाले जिलों में सम्मिलित है तथा यहाँ औद्योगिक निवेश एवं नगरीय विस्तार निरंतर बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में यह समझना आवश्यक है कि यह परिवर्तन जिले के सामाजिक ताने-बाने को किस दिशा में प्रभावित कर रहा है। यह अध्ययन नगर एवं ग्राम नियोजन से जुड़े अधिकारियों, नीति-निर्माताओं तथा समाजशास्त्रीय शोधार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि इससे शहरीकरण एवं औद्योगीकरण के सामाजिक परिणामों को समझते हुए संतुलित विकास की रणनीति तैयार करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही यह अध्ययन परिवार, व्यवसाय एवं लिंग संबंधी सामाजिक परिवर्तन के सैद्धांतिक विश्लेषण में भी योगदान देगा।

शोध प्रविधि-

प्रस्तुत अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि पर केंद्रित है। अध्ययन हेतु आवश्यक आँकड़े भारत की जनगणना (1991, 2001, 2011) के प्रतिवेदनों, जिला जनगणना पुस्तिका रीवा, मध्यप्रदेश आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के प्रतिवेदनों, जिला उद्योग केंद्र रीवा के अभिलेखों, नगर निगम रीवा तथा जिला पंचायत रीवा के वार्षिक प्रतिवेदनों एवं संबंधित विषय पर प्रकाशित शोध-पत्रों तथा पुस्तकों से संग्रहित किए गए हैं। संग्रहित आँकड़ों को सुसंगत रूप से सारणीबद्ध कर प्रतिशत विधि एवं प्रवृत्ति-विश्लेषण के माध्यम से उनका विश्लेषण किया गया है। जहाँ आवश्यक हुआ है, वहाँ वर्ष 2021 के आँकड़ों को उपलब्ध प्रवृत्तियों के आधार पर अनुमानित रूप में प्रस्तुत किया गया है। विश्लेषण के निष्कर्षों की व्याख्या समाजशास्त्रीय सिद्धांतों, विशेष रूप से सामाजिक परिवर्तन एवं संरचनात्मक-प्रकार्यवाद के परिप्रेक्ष्य में की गई है।

रीवा जिले में शहरीकरण एवं औद्योगीकरण का विश्लेषण-

इस भाग में द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर रीवा जिले में शहरीकरण एवं औद्योगीकरण की प्रवृत्ति तथा उसके सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का सारणीबद्ध विश्लेषण एवं व्याख्या प्रस्तुत की गई है।

रीवा जिले में नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की प्रवृत्ति-

सारणी 1

रीवा जिले में जनसंख्या का दशकीय वितरण (1991-2021)

वर्ष	कुल जनसंख्या	नगरीय जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या	नगरीय जनसंख्या (%)
1991	19,77,000	1,76,000	18,01,000	8.9
2001	21,87,000	2,34,000	19,53,000	10.7
2011	23,64,000	3,28,000	20,36,000	13.9
2021 (अनुमानित)	25,42,000	4,32,000	21,10,000	17.0

स्रोत-जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, जिला रीवा

सारणी 1 से स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में सन् 1991 से 2021 की अवधि में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 8.9 प्रतिशत से बढ़कर 17.0 प्रतिशत तक पहुँच गया है, अर्थात् तीन दशकों में यह लगभग दोगुना हो गया है। इसके विपरीत ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत निरंतर घटता गया है। यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, शिक्षा एवं प्रशासनिक सेवाओं के विस्तार तथा रोजगार के नगरीय अवसरों में वृद्धि के कारण जिले में ग्रामीण-नगरीय प्रवास की गति निरंतर तेज हुई है, जो शहरीकरण की सामान्य समाजशास्त्रीय प्रक्रिया के अनुरूप है।

रीवा जिले में औद्योगीकरण की स्थिति-

सारणी 2

रीवा जिले में प्रमुख औद्योगिक इकाइयों का वर्गीकरण

उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	कार्यरत श्रमिकों की संख्या
सीमेंट उद्योग	4	3,200
ताप/ऊर्जा उत्पादन इकाइयाँ	3	2,100
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	38	1,450
हस्तशिल्प एवं लघु उद्योग	210	2,600
अन्य विनिर्माण इकाइयाँ	65	1,150
योग	320	10,500

स्रोत-जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र रीवा

सारणी 2 के अनुसार रीवा जिले में सीमेंट उद्योग एवं ताप/ऊर्जा उत्पादन इकाइयाँ यद्यपि संख्या में सीमित हैं, तथापि इनमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है, जो इन बड़े उद्योगों की उच्च रोजगार-क्षमता को दर्शाता है। इसके साथ ही हस्तशिल्प एवं लघु उद्योगों की संख्या सर्वाधिक (210) है, जो स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। कुल मिलाकर जिले में 320 औद्योगिक इकाइयों में लगभग 10,500 श्रमिक कार्यरत हैं, जो जिले की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र के बढ़ते महत्व को स्पष्ट करता है।

व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन-

सारणी 3

रीवा जिले में व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन (1991 एवं 2021)

क्षेत्र	1991 (%)	2021 (अनुमानित) (%)
कृषि क्षेत्र	78.0	54.0
औद्योगिक क्षेत्र	8.0	19.0
सेवा क्षेत्र	14.0	27.0
योग	100.0	100.0

स्रोत-जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र रीवा

सारणी 3 से स्पष्ट होता है कि सन् 1991 में जिले के कार्यबल का 78.0 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र पर निर्भर था, जो 2021 में घटकर 54.0 प्रतिशत रह गया है। इसके विपरीत औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत 8.0 से बढ़कर 19.0 तथा सेवा क्षेत्र का प्रतिशत 14.0 से बढ़कर 27.0 हो गया है। यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि औद्योगीकरण एवं नगरीय विस्तार के कारण जिले की व्यावसायिक संरचना कृषि-प्रधान से क्रमशः औद्योगिक एवं सेवा-प्रधान संरचना की दिशा में अग्रसर हो रही है।

परिवार संरचना पर प्रभाव-

सारणी 4

रीवा जिले में परिवार संरचना में परिवर्तन (शहरीकरण-पूर्व एवं वर्तमान)

परिवार का प्रकार	शहरीकरण-पूर्व स्थिति (लगभग 1991) (%)	वर्तमान स्थिति (2021) (%)
संयुक्त परिवार	68.0	41.0
एकल/नाभिकीय परिवार	32.0	59.0
योग	100.0	100.0

स्रोत-नगर निगम रीवा (2023). वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन। रीवा (म.प्र.)

सारणी 4 से स्पष्ट होता है कि सन् 1991 के आसपास जिले में लगभग 68.0 प्रतिशत परिवार संयुक्त परिवार के रूप में संगठित थे, जबकि वर्तमान में यह प्रतिशत घटकर 41.0 रह गया है तथा एकल अथवा नाभिकीय परिवारों का प्रतिशत 32.0 से बढ़कर 59.0 हो गया है। यह परिवर्तन शहरीकरण एवं औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप रोजगार हेतु परिवार के सदस्यों के पृथक नगरीय क्षेत्रों में प्रवास, आवासीय सीमाओं तथा आर्थिक स्वतंत्रता की बढ़ती आवश्यकता का परिणाम है, जो संरचनात्मक-प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से पारंपरिक संयुक्त परिवार व्यवस्था के विघटन की सामान्य सामाजिक प्रक्रिया के अनुरूप है।

शिक्षा एवं साक्षरता पर प्रभाव-

सारणी 5

रीवा जिले में साक्षरता दर की प्रवृत्ति (1991-2021)

वर्ष	साक्षरता दर (%)
1991	44.2
2001	61.4
2011	71.6
2021 (अनुमानित)	78.3

स्रोत-जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, जिला रीवा

सारणी 5 के अनुसार रीवा जिले की साक्षरता दर सन् 1991 में 44.2 प्रतिशत से निरंतर वृद्धि करते हुए 2021 में अनुमानतः 78.3 प्रतिशत तक पहुँच गई है। शिक्षा संस्थानों के विस्तार, नगरीय क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं की सुगम उपलब्धता तथा औद्योगिक क्षेत्र में कुशल एवं शिक्षित श्रमशक्ति की बढ़ती माँग ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे स्पष्ट होता है कि शहरीकरण एवं औद्योगीकरण का शिक्षा के प्रसार पर प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक भूमिका पर प्रभाव-

सारणी 6

रीवा जिले में महिला श्रमशक्ति सहभागिता दर की प्रवृत्ति (1991-2021)

वर्ष	महिला श्रमशक्ति सहभागिता दर (%)
------	---------------------------------

1991	18.6
2001	22.4
2011	27.8
2021 (अनुमानित)	33.5

स्रोत-जिला श्रम कार्यालय, जिला रीवा

सारणी 6 से स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में महिला श्रमशक्ति सहभागिता दर सन् 1991 में 18.6 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में अनुमानतः 33.5 प्रतिशत तक पहुँच गई है। खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प तथा सेवा क्षेत्र में महिलाओं हेतु उपलब्ध रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा शिक्षा के प्रसार ने महिलाओं की आर्थिक सहभागिता को प्रोत्साहित किया है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि शहरीकरण एवं औद्योगीकरण ने पारंपरिक रूप से घरेलू भूमिका तक सीमित महिलाओं को सार्वजनिक एवं आर्थिक क्षेत्र में सहभागी बनाने में सहायक भूमिका निभाई है।

शहरीकरण एवं औद्योगीकरण से उत्पन्न सामाजिक समस्याएँ-

सारणी 7

रीवा जिले में शहरीकरण एवं औद्योगीकरण से संबद्ध प्रमुख सामाजिक समस्याओं की प्रवृत्ति

समस्या का प्रकार	1991-2011 की प्रवृत्ति	2011-2021 की प्रवृत्ति
मलिन बस्तियों का विस्तार	क्रमिक वृद्धि	उल्लेखनीय वृद्धि
यातायात एवं भीड़भाड़ की समस्या	सीमित वृद्धि	उल्लेखनीय वृद्धि
वायु एवं जल प्रदूषण	क्रमिक वृद्धि	उल्लेखनीय वृद्धि

संयुक्त परिवार विघटन	क्रमिक वृद्धि	निरंतर वृद्धि
पारंपरिक सामाजिक नियंत्रण में कमी	आंशिक कमी	उल्लेखनीय कमी

स्रोत-नगर निगम रीवा (2023). वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन। रीवा (म.प्र.)

सारणी 7 से स्पष्ट होता है कि शहरीकरण एवं औद्योगीकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ रीवा जिले में मलिन बस्तियों का विस्तार, यातायात एवं भीड़भाड़ की समस्या तथा वायु एवं जल प्रदूषण की समस्याओं में क्रमशः वृद्धि हुई है, विशेष रूप से वर्ष 2011 के पश्चात इनकी गति और तीव्र हुई है। इसके साथ ही संयुक्त परिवार व्यवस्था के विघटन एवं पारंपरिक सामाजिक नियंत्रण के कमजोर होने की प्रवृत्ति भी निरंतर बनी हुई है। यह स्पष्ट करता है कि शहरीकरण एवं औद्योगीकरण के सकारात्मक आर्थिक प्रभावों के साथ-साथ इसके कुछ अनियोजित एवं प्रतिकूल सामाजिक परिणाम भी सामने आए हैं, जिनके समाधान हेतु नियोजित नगरीय एवं औद्योगिक विकास की आवश्यकता है।

निष्कर्ष-

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि विगत तीन दशकों में रीवा जिले में शहरीकरण एवं औद्योगीकरण की प्रक्रिया ने जिले के सामाजिक जीवन को बहुआयामी रूप से प्रभावित किया है। द्वितीयक आँकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि जिले की नगरीय जनसंख्या, औद्योगिक इकाइयों की संख्या, साक्षरता दर एवं महिला श्रमशक्ति सहभागिता में निरंतर वृद्धि हुई है तथा व्यावसायिक संरचना कृषि-प्रधान से औद्योगिक एवं सेवा-प्रधान स्वरूप की ओर अग्रसर हुई है। इसके साथ ही पारंपरिक संयुक्त परिवार व्यवस्था के स्थान पर एकल अथवा नाभिकीय परिवारों की संख्या में वृद्धि तथा पारंपरिक सामाजिक नियंत्रण में कमी भी परिलक्षित हुई है। इसके समानांतर मलिन बस्तियों के विस्तार, यातायात भीड़भाड़ एवं पर्यावरणीय

प्रदूषण जैसी सामाजिक समस्याएँ भी उभरी हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि शहरीकरण एवं औद्योगीकरण ने रीवा जिले के सामाजिक जीवन में आधुनिकीकरण एवं आर्थिक अवसरों की दृष्टि से सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं, परंतु इसके साथ उत्पन्न सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु नियोजित एवं संतुलित विकास रणनीति अपनाना आवश्यक है।

सुझाव-

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर यह सुझाव दिया जाता है कि रीवा जिले में नगरीय एवं औद्योगिक विस्तार को नियोजित ढाँचे के अंतर्गत संचालित किया जाना चाहिए, जिससे मलिन बस्तियों के अनियंत्रित विस्तार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके तथा नगरीय अधोसंरचना का समुचित विकास सुनिश्चित हो सके। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के समय पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए, जिससे वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित किया जा सके। परिवार संरचना में हो रहे परिवर्तनों के मध्य वृद्ध एवं आश्रित सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सामुदायिक एवं संस्थागत सहायता तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं की बढ़ती आर्थिक सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुए उनके लिए सुरक्षित कार्य-परिस्थितियों, समान वेतन एवं कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अंततः यह भी सुझाव दिया जाता है कि यातायात प्रबंधन एवं सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का विस्तार करते हुए नगर नियोजन में सामाजिक समावेशन के सिद्धांत को समुचित स्थान दिया जाए, जिससे शहरीकरण एवं औद्योगीकरण के लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँच सकें।

संदर्भ-

1. जनगणना निदेशालय (1991, 2001, 2011). जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, रीवा। भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मध्यप्रदेश शासन (2023). मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, भोपाल।
3. जिला उद्योग केंद्र, रीवा (2023). वार्षिक प्रतिवेदन एवं औद्योगिक इकाइयों का अभिलेख। रीवा (म.प्र.)।
4. नगर निगम रीवा (2023). वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन। रीवा (म.प्र.)।
5. जिला पंचायत रीवा (2023). जिला वार्षिक योजना प्रतिवेदन, रीवा (म.प्र.)।
6. पाण्डेय, एस.एन. (2019). भारत में शहरीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन। रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
7. शर्मा, के.एल. (2018). ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर।
8. मिश्रा, बी.बी. (2020). औद्योगीकरण एवं परिवार संरचना में परिवर्तन। न्यू सेंचुरी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
9. भारत सरकार (2023). आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. अहिरवार, पी.के. (2017). शहरीकरण, औद्योगीकरण एवं सामाजिक समस्याएँ। अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।